

≈ ग्रामीण ≈ औद्योगीकरण

आत्मनिर्भर भारत के लिए आधारभूत सोपान



परिचय

वर्तमान में ग्रामीण उद्योग भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, विरासत और अद्वितीय शिल्प कौशल के साथ-साथ दस्तकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल अति आवश्यक गैर-कृषि रोजगार सृजित करने में योगदान देते हैं, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने की भी क्षमता रखते हैं।

ग्रामीण उद्योगों के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। इस प्रयास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए— खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने विनिर्माण व सेवा इकाइयों की स्थापना में अभूतपूर्व वृद्धि प्राप्त की है, कृषि उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन सबके बावजूद भी यह क्षेत्रक अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने में बाधाओं का सामना कर रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि—

- ग्रामीण उद्योग क्या हैं और राष्ट्रीय विकास के लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं;
- स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण उद्योगों के लिए सरकार की नीतिगत रूपरेखा कैसे विकसित हुई है;
- इन उद्योगों को समर्थन एवं बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;
- इन उद्योगों को अपनी संवृद्धि व विकास के मार्ग में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; तथा
- ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

ग्रामीण उद्योग क्या हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं?

- ग्रामीण उद्योग गैर-कृषि गतिविधियों से संबंधित होती हैं। ये ग्रामीण संसाधनों पर निर्भर होते हैं। इनका उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, श्रम बल एवं स्वदेशी या घरेलू प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से रोजगार सृजन करना होता है।
- ग्रामीण उद्योग सामान्यतः जनता द्वारा उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये मुख्यधारा के उद्योगों के विपरीत हैं, जहां वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।
- इन उद्योगों को लोकप्रिय रूप से लघु उद्योग, ग्रामोद्योग या दस्तकारी उद्योग कहा जाता है।
- इस प्रकार, ग्रामीण औद्योगीकरण एक अवधारणा है। इसके अंतर्गत गरीबों के निवास के निकट ही गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाते हैं।



ग्रामीण उद्योगों के प्रकार



पारंपरिक ग्रामोद्योग

खादी, कुटीर, चर्मशोधन, लकड़ी का काम, दस्तकारी उद्योग आदि।



हल्के उद्योग

पशु चारा और पशु आहार उद्योग, स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए निर्माण कार्यक्रम आदि।



मध्यम समूह उद्योग

ऊर्जा के लिए शीरा या कोयले का उपयोग करने वाले लघु सीमेंट संयंत्र, लघु कागज निर्माण संयंत्र आदि।



भारी उद्योग

जैव-उर्वरक संयंत्र, जैव-कीटनाशक संयंत्र, लघु इस्पात संयंत्र आदि।



सनराइज क्षेत्रक

खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण पर्यटन सहित कृषि व्यवसाय आदि।

◆ राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण क्या भूमिका निभाता है? ◆

❖ **ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण:** ग्रामीण औद्योगीकरण कुशल एवं अकुशल रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है, ग्रामीण व्यवसायों में विविधता लाता है, आय व जीवन स्तर में वृद्धि करता है, शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को कम करता है तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।

❖ **कृषिगत मजदूरों की समस्याओं का समाधान:** ये उद्योग, अतिरिक्त एवं गैर-मौसमी रोजगार उपलब्ध कराकर लघु, सीमांत और काश्तकार किसानों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार ये उद्योग इनकी अल्प कृषि आय के बेहतर विकल्प बनते हैं। ज्ञातव्य है कि लघु, सीमांत और काश्तकार किसान 80% से अधिक कृषि कार्यबल का गठन करते हैं।

❖ **समावेशी राष्ट्रीय विकास:** ग्रामीण औद्योगीकरण कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को सुगम बना सकता है। इसके अतिरिक्त, इसमें राष्ट्रीय आय का समान वितरण करने की भी क्षमता है।

❖ **संतुलित औद्योगीकरण:** ग्रामीण औद्योगीकरण पहले से ही विकसित शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास के संकेंद्रण को रोकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाता है। इस प्रकार, यह क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को कम करने में मदद करता है।

❖ **भारत की समृद्ध संस्कृति का संरक्षण:** ग्रामीण औद्योगीकरण देश के शिल्प कौशल और कला परंपरा को संरक्षित करने में मदद करेगा, जो कई पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली है।

❖ **कश्मीर की पश्मीना शॉल, जयपुर के नीले मिट्टी के बर्तन (मृद्भाण्ड), फिरोजाबाद की चूड़ियां, आंध्र प्रदेश के एटिकोप्पका खिलौने आदि गाँवों में आज भी जीवंत पारंपरिक औद्योगिक गतिविधियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।**

❖ **सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना:** वर्तमान में, भारत में लगभग 20% सूक्ष्म और लघु-उद्यम (MSEs) इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये इकाइयां बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए सहायक उद्योग के रूप में कार्य करती हैं।

❖ ग्रामीण औद्योगीकरण लाभदायक व्यावसायिक विचारों को लागू करने हेतु इन उद्यमों के लिए निवेश आकर्षित कर सकता है।

❖ **महिला सशक्तीकरण:** ग्रामीण औद्योगीकरण महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर सकता है। उल्लेखनीय है कि कृषि श्रमबल के नारीकरण और कृषि योग्य भूमि के विस्तार की घटती संभावनाओं के कारण ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

❖ **सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना:** स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल और स्थानीय उपभोग के साथ ग्रामीण उद्योग संसाधनों के किफायती उपयोग व संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। साथ ही, इनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। दूसरी ओर ग्रामीण आय में वृद्धि असमानता को कम कर सकती है और स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही, ग्रामीण कार्यबल का ग्रामीण क्षेत्रों में ही समावेश गैर-टिकाऊ शहरी विकास की बढ़ती समस्या को भी हल कर सकता है।



ग्रामीण औद्योगीकरण: गरीबी उन्मूलन की कुंजी

❖ **ग्रामीण अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण उच्च उत्पादक रोजगार सृजित कर सकता है। इससे अधिकतर परिवार गरीबी से बाहर निकल सकते हैं।**

❖ RBI के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण बेरोजगारी में अधिक कमी करने वाले राज्य वित्त वर्ष 2004-05 से वित्त वर्ष 2011-12 के बीच गरीबी उन्मूलन में भी सफल हुए हुए हैं। ये राज्य हैं— गोवा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और पंजाब।

❖ **केस स्टडी: केरल का ग्रामीण रूपांतरण मॉडल—** ऐतिहासिक रूप से केरल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध रहा है। इसके कारण यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार (विशेष रूप से ग्रामीण विनिर्माण में) की उच्च उपलब्धता रही है।

❖ इनमें से कुछ संसाधनों को औद्योगिक वस्तुओं में प्रसंस्कृत किया गया था। ये वस्तुएं व्यापक रूप से बाह्य बाजारों से जुड़ी हुई थीं।

❖ वर्ष 1971-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण के कारण 100 से अधिक गांव शहरी क्षेत्रों में रूपांतरित हो गए थे।

स्टडी: डेयरी उद्यमों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

❖ **भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 23 प्रतिशत है। मूल्य के संदर्भ में दूध देश की सबसे बड़ी कृषिगत वस्तु है। इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत का योगदान है।**

❖ इस उपलब्धि का श्रेय मुख्य रूप से महिला डेयरी किसानों को जाता है। ये भारत के डेयरी क्षेत्र के 70 प्रतिशत कार्य बल का प्रतिनिधित्व करती हैं। डेयरी सहकारी समितियों की एक तिहाई से अधिक सदस्य महिलाएं हैं।

❖ डेयरी व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वप्रेरित सूक्ष्म-उद्यमी बनने में सक्षम बनाया है।

बदलती जलवायु के बीच ग्रामीण औद्योगीकरण: इसकी संधारणीयता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है?

हालांकि, पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, लेकिन उनकी संधारणीयता आर्थिक और ग्रामीण विकास नीतियों पर निर्भर करती है।

❖ वियतनाम इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिशील किंतु अनियंत्रित औद्योगीकरण ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को जन्म दिया है।

❖ वियतनाम में नवीनीकरण की नीति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्प गांवों और औद्योगिक समूहों का तेजी से विकास हुआ है। इससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है और गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है।

❖ हालांकि, मजबूत पर्यावरण नीति के बिना शिल्प गांवों का तेजी से विस्तार हो रहा है और बाजार की प्रतिस्पर्धा भी तीव्रता से बढ़ रही है। इसने पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों के अपक्षय की समस्या को जन्म दिया है, जैसे— विशेष रूप से रेड रिवर डेल्टा के आस-पास वनों की कटाई आदि। इसका जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

❖ उपर्युक्त उदाहरण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल औद्योगीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, लेकिन निम्नलिखित कारक ग्रामीण उद्योगों को जलवायु के अनुकूल बनाने से रोकते हैं:

❖ जलवायु परिवर्तन हेतु निर्मित ग्रामीण नीतियों में कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि अन्य उद्योगों की उपेक्षा की जाती है।

❖ स्थानीय स्तर के प्रशासन के पास प्रायः स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के प्रबंधन के लिए ज्ञान, क्षमता, कौशल और धन की कमी होती है।

❖ सीमित आर्थिक संसाधन और दूरी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के विकल्पों को कम करते हैं।

❖ निम्न गुणवत्ता वाली भौतिक और डिजिटल अवसंरचना।

❖ इस प्रकार, ग्रामीण औद्योगीकरण नीति के तहत निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए:

❖ शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु स्थानीय क्षमता का निर्माण करना।

❖ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

❖ संधारणीय भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना।

❖ पारितंत्र सेवाओं का उच्चतर मूल्य निर्धारण करना।

❖ चक्रीय (सर्कुलर) और जैव-अर्थव्यवस्था में तेजी लाना।

❖ परिवहन क्षेत्र का विकार्षनीकरण करना।

भारत में ग्रामीण उद्योग प्राचीन काल से ही विद्यमान थे। हालांकि, इनके महत्व के बावजूद इन उद्योगों को (विशेष रूप से ब्रिटिश काल के दौरान) गिरावट के दौर का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद इन उद्योगों के विकास लिए सरकार ने कई नीतिगत उपाय किए।

स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण उद्योगों के लिए नीतिगत ढांचा कैसे विकसित हुआ है?

भारत में नीति निर्माताओं ने ग्रामीण औद्योगीकरण को हमेशा योजना निर्माण के केंद्र में रखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नीति का मुख्य फोकस ग्रामीण उद्योगों के संरक्षण से उनके विकास तथा अंततः उनके संवर्धन की ओर स्थानांतरित हो गया है।

❖ ग्रामीण उद्योगों का संरक्षण:

❖ औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध छोटे उद्यमियों की सुरक्षा पर बल दिया गया था।

❖ प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में कुछ विशेष श्रेणी के स्टोर्स के लिए केवल गांवों से और छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की खरीद करना अनिवार्य कर दिया गया था। इन स्टोर्स को इन वस्तुओं के मूल्य में बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में कुछ अंतर रखने की भी अनुमति दी गई थी।

❖ ग्रामीण उद्योगों का विकास:

❖ कर्वे समिति की रिपोर्ट, 1955 और औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 ने ग्रामीण उद्योगों के आत्मनिर्भर होने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ इनके एकीकृत विकास के लिए पर्याप्त व्यवहार्यता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था।

❖ तदनुसार, विभिन्न चुनौतियों की पहचान की गई और ग्रामीण एवं पारंपरिक उद्योगों के विकास के लिए अलग-अलग प्रोत्साहनों पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार, औद्योगिक सहकारी समितियों का संगठन, कौशल विकास आदि।

स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण औद्योगीकरण का बदलता स्वरूप



ब्रिटिश काल से पहले प्राचीन काल से ही भारत के ग्रामीण समाज में जाति के आधार पर दस्तकारी उद्योग स्थापित किए जाते रहे हैं जहां वंशजों को आवश्यक कौशल विरासत में मिलते थे। "कृषि और हस्तशिल्प का सम्मिश्रण" पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता थी।



ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश युग की शुरुआत के दौरान कृषि और हस्तशिल्प के बीच संतुलन बिगड़ गया और 18वीं शताब्दी के बाद ग्रामीण उद्योगों का पतन शुरू हो गया। इस प्रक्रिया को 'विऔद्योगीकरण' के नाम से जाना गया।

ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन:

- तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना ग्रामीण उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित थी।
- औद्योगिक नीति संकल्प, 1977 कुटीर और लघु उद्योगों (SSIs) को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। बाद में वर्ष 1980 और 1990 के औद्योगिक नीति संकल्प द्वारा उनकी संवृद्धि का समर्थन करने हेतु निवेश सीमा में बढ़ोतरी की गई थी।
- परिणामस्वरूप, इन उद्योगों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और उनके विपणन का समर्थन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना की गई थी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) अधिनियम, 2006 ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे MSMEs को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिए सक्षमकारी नीतिगत माहौल प्रदान करता है।



क्या आप जानते हैं?

- प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत में पारंपरिक उद्योग निर्यात में एक प्रमुख भागीदार थे।
- अथर्ववेद इंगित करता है कि एक प्रकार का ऊनी कपड़ा जिसे दूर्श (Dursh) कहा जाता था, व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी।
- मध्यकालीन भारत के दौरान ढाका के मलमल, मुर्शिदाबाद के रेशम, सिलहट की हाथीदांत नक्काशी और कटक के आभूषण नक्काशी के काम की प्राचीन फारसियों, यूनानियों तथा रोमन वासियों ने प्रशंसा की थी।

कुटीर उद्योग बनाम लघु उद्योग

- कुटीर उद्योग सामान्यतः छोटे घरों या आवासीय स्थलों में स्थापित होते हैं। इन उद्योगों में पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है और ये उत्पादन की पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर होते हैं।
- लघु स्तरीय उद्योग (SSI) ऐसे उद्योग हैं, जिनमें लघु या सूक्ष्म पैमाने पर वस्तुओं का विनिर्माण व उत्पादन किया जाता है या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपये तक है और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये तक का है। इन उद्योगों में आधुनिक और पारंपरिक दोनों तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- कुटीर और लघु उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) अनेक योजनाओं को लागू करके इसमें राज्य सरकारों की सहायता करता है।

सक्रिय ग्रामीण औद्योगीकरण

उपर्युक्त नीतिगत समर्थन और सक्षमकारी परिवेश के साथ, गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न लघु उद्योग वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन हैं।

आर्थिक योगदान

- सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी: अर्थव्यवस्था में कुल निवल मूल्य वर्धित (NVA) का 47.7% ग्रामीण भारत से आता है।
 - विनिर्माण: कुल NVA का 51.2% योगदान करता है।
 - खनन: NVA का 53.4% योगदान करता है।
 - परिवहन: NVA का 47.9% योगदान करता है।
- ग्रामीण आय: ग्रामीण आय का लगभग दो तिहाई भाग गैर-कृषि गतिविधियों से सृजित होता है।
- रोजगार सृजन में हिस्सेदारी: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 38वें दौर और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) (2018-19) रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार का योगदान 42% है। यह वर्ष 1983 में केवल 19% था।
- बाह्य आघातों के प्रति लचीलापन: भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी ग्रामीण व्यवसाय विश्वास सूचकांक (Rural Business Confidence Index) के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के बावजूद ग्रामीण भारत में खुदरा तथा वाणिज्यिक ऋणों के वितरण में मात्रा के अनुसार क्रमशः 30% और 100% की वृद्धि देखी गई थी।

देश में ग्रामीण उद्योगों में दर्ज की गई संवृद्धि एवं विकास के बावजूद इनके समक्ष कुछ पहले से विद्यमान एवं कुछ उभरती हुई चुनौतियां व्याप्त हैं। ये चुनौतियां इनकी भावी संवृद्धि में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और इन्हें अपनी वास्तविक क्षमता का दोहन करने से रोक रही हैं।

ग्रामीण उद्योगों की सफलता की राह में प्रमुख बाधाएं क्या हैं?

- ❖ **संरक्षण के कारण बेहतर स्पर्धा न कर पाना:** 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद घरेलू बाजार में लघु उद्योगों (SSIs) के लिए आरक्षित मर्दों को आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। हालांकि, सुरक्षात्मक नीतियों के कारण अधिकांश SSIs ने परिवर्तित हो रही मांगों के अनुरूप स्वयं को उन्नत नहीं किया।
- ❖ **ऋण तक पहुंच:** ऋण की उपलब्धता हमेशा एक बड़ी बाधा रही है, लेकिन बदलते आर्थिक परिदृश्य में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने की अनिवार्यता, कच्चे माल की खरीद तथा अंतिम उत्पादों के विपणन में बढ़ती कठिनाइयों के कारण ऋण की आवश्यकता और अधिक बढ़ती जा रही है।
 - ❖ उदाहरण के लिए, 9,750 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित ऋण आवश्यकताओं के मुकाबले ग्रामीण दस्तकारों को मुश्किल से 100 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं।
- ❖ **अपर्याप्त विपणन अवसंरचना:** खराब परिवहन अवसंरचना, विपणन संचार में बाधाएं (जैसे सीमित साक्षरता दर), पर्याप्त और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का अभाव, गांवों का दूर-दूर स्थित होना आदि ग्रामीण बाजारों तक पहुंच को कम करते हैं। इस प्रकार **पारंपरिक उत्पादों के लिए शहरी क्षेत्रों में मांग उत्पन्न नहीं हो पाती है।**
- ❖ **कच्चे माल की खरीद:** अर्थव्यवस्था के बढ़ते व्यवसायीकरण, ग्रामीण कच्चे माल (जैसे चमड़ा, स्प्लिट व विनियर, बांस, अखाद्य तेल एवं ऊन) पर आधारित उच्च प्रौद्योगिकी वाले शहरी उद्योगों के विकास के कारण स्थानीय दस्तकार और उद्यमी अपने आदान (इनपुट) बाजार से वंचित हो गए हैं।
- ❖ **तकनीकी बाधाएं:** इनमें से अधिकतर उद्योग उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से ग्रस्त हैं। इसके साथ ही, **कौशल और तकनीकी ज्ञान की कमी** के कारण उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाने में असमर्थता एक अन्य चुनौती है।
- ❖ उदाहरण के लिए, **फिरोजाबाद** 200 से अधिक वर्षों से कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। यह शहर विश्व में **कांच की चूड़ियों** का सबसे बड़ा निर्माता है। यहां एक सुरक्षा संबंधी समस्या है। वह यह कि इन कारखानों में कार्य करने वाले **मजदूर कांच को पिघलाते समय सामान्यतः किसी भी सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वे सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग में निपुण नहीं हैं।**
- ❖ **मानव संसाधन संबंधी चुनौतियां:** बुनियादी सुविधाओं की कमी और ग्रामीण-शहरी वेतन असमानता जैसे कारणों से ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को बनाए रखने या बाहर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने में भी असमर्थ हैं। इस प्रकार, ग्रामीण उद्यमों के पास प्रायः निम्न कौशल युक्त या अकुशल श्रम बल होता है। साथ ही, अनुभवी और सक्षम प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय कर्मियों का भी अभाव होता है।

ओडिशा की संबलपुर साड़ी: भारत की शान, बुनकरों की कठिन परीक्षा

- ❖ संबलपुर साड़ियों को **हथकरघों पर बुना जाता है।** इकत तकनीक का उपयोग करके, शंख, चरखों और फूलों का रूपांकन इस वस्त्र शिल्प की विशेषता है।
- ❖ एक संबलपुरी साड़ी को पूरा करने के लिए 2-3 बुनकरों को कम-से-कम 4-5 दिन लगते हैं।
- ❖ इस साड़ी को वर्ष 2010 में भौगोलिक संकेतक (G.I.) दर्जा दिया गया था। हालांकि, इनकी सस्ती नकली प्रतिकृतियां बाजार में आने के कारण हथकरघा बुनकर अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। ये नकली प्रतिकृतियां उनकी आजीविका के लिए खतरा बन गई हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त, इन बुनकरों को अपर्याप्त पारिश्रमिक, कौशल विकास प्रशिक्षण की कमी और अपने उत्पादों के संरक्षण के अभाव का सामना करना पड़ रहा है।
- ❖ कुछ दशक पहले, इस क्षेत्र में लगभग 100 परिवार संबलपुरी साड़ी बुनते थे, लेकिन वर्तमान में कुछ ही परिवार बचे हैं।



चुनौतियों से निपटने और ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी पहलें की गई हैं?

औपचारिक संस्थागत व्यवस्था	❖ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC): इसे वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना करना, उनके विकास की योजना तैयार करना, उनका प्रचार-प्रसार करना, उन्हें सहयोग देना, सुसंगठित करना तथा सहायता प्रदान करना है। ❖ यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), पारंपरिक उद्योगों के पुनः सृजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति/SFURTI), बाजार संवर्धन विकास सहायता (MPDA), मधुमक्खी पालन, पॉटरी कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी है। ❖ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) लिमिटेड: इसकी स्थापना वर्ष 1955 में लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। ❖ यह बैंक ऋण सुविधा, कच्चे माल हेतु सहायता, निर्यात सहायता, प्रदर्शनियों के आयोजन (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों), सूचना सेवा प्रदान करने आदि में संलग्न है।
पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना	❖ पारंपरिक उद्योगों के पुनः सृजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति/SFURTI). ❖ विकास के लिए पारंपरिक कलाओं-शिल्पों में कौशलों का उन्नयन और प्रशिक्षण योजना (उस्ताद/USTTAD).
लघु उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं को सुगम बनाना	❖ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD): यह लघु उद्योगों (SSIs), कुटीर और ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्पों व अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्धन एवं विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। साथ ही, उन्हें विनियमित भी करता है। ❖ नाबार्ड के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज प्रोग्राम ग्राहक आधार और पहुंच के मामले में अब विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म-वित्तीय (माइक्रोफाइनेंस) कार्यक्रम बन गया है। ❖ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI): इसकी स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों (SSIs) को समय पर, पर्याप्त और वहनीय ऋण प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ❖ मुख्य रूप से ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना। ❖ वर्तमान में देश में डेयरी, उर्वरक, चीनी मिल आदि क्षेत्रों में 8.54 लाख सहकारी इकाइयां कार्य कर रही हैं।
प्रशिक्षण प्रदान करना और कौशल विकास करना	❖ नाबार्ड के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPs) और आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम (LEDPs). ❖ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (RSETI). ❖ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU - GKY). ❖ देश भर में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) / शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS).
कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना	❖ नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना (एस्पायर/ASPIRE): यह योजना कृषि आधारित उद्योगों के लिए आजीविका व्यापार इनक्यूबेटर (LBI) या प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ❖ कृषि अवसंरचना कोष (AIF): यह कोष फसल कटाई के बाद प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मध्यम अवधि की ऋण सुविधा प्रदान करता है। ❖ किसान उत्पादक संगठन (FPOs): इसका उद्देश्य बड़े इकोनॉमी ऑफ़ स्केल का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार हेतु समूह तैयार करना है। ❖ आधुनिक बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना चलाई जा रही है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना	❖ कृषि हेतु पूरक व्यवस्था करने, प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिकीकृत करने और कृषि-अपशिष्ट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम. संपदा) ❖ मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (PMFME) योजना। ❖ विदेशों में ब्रांडिंग और प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार के लिए खाद्य विनिर्माण संस्थाओं की सहायता हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)।

उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना	❖ विकेंद्रीकृत इन्क्यूबेशन सेंटर: अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC) को स्टार्टअप और इनोवेशन इको-सिस्टम के संबंध में सेवा से वंचित या कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए स्थापित किया गया है। ❖ स्टार्टअप इंडिया योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत सूक्ष्म उद्यमों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जाती है और उन्हें संबंधित लाभ प्रदान किए जाते हैं। ❖ नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ❖ राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष की स्थापना की गई है।
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना	❖ स्टैंड-अप इंडिया योजना। ❖ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पहचाने गए ग्रामीण गरीब परिवार से कम-से-कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के तहत लाया जाए।
अवसंरचना निर्माण	❖ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन-ग्रामीण आदि। ❖ स्थानीय इकाइयों को अवसंरचना संबंधी सहायता और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र (RISC) स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे उनकी उत्पादन क्षमता, कौशल उन्नयन और बाजार को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
डिजिटल सशक्तीकरण के लिए पहले	❖ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ❖ ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने हेतु भारतनेट परियोजना। ❖ राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM): यह कृषि उत्पादों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए कृषि उपज बाजार समिति (APMC) मंडियों को आपस में जोड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियां: ग्रामीण उद्योगों को सहायता या अतिरिक्त चुनौती?

उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, उनमें निश्चित रूप से ग्रामीण व्यवसाय को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता है। इस संबंध में, निम्नलिखित घटनाक्रम ध्यान देने योग्य हैं:

❖ **डिजिटल कृषि:** इसमें सूचना और संचार तकनीक (ICT) तथा डेटा पारितंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य समय पर लक्षित सूचना व सेवाओं का विकास तथा वितरण सुनिश्चित करना है। इससे सभी को सुरक्षित, पौष्टिक व किफायती भोजन प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही, कृषि को लाभदायक और संधारणीय भी बनाया जा सकेगा। ये सभी प्रौद्योगिकियां **परिशुद्ध खेती (Precision Farming)** की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, संसाधनों का संधारणीय उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि आदि की संभावना बढ़ जाती है।

❖ **भारत में डिजिटल कृषि से संबंधित पहले**

□ डिजिटल कृषि मिशन 2021-2025: नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को समर्थन और गति प्रदान करना। इन तकनीकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक तथा ड्रोन व रोबोट का उपयोग आदि शामिल है।

□ कृषि डिजिटल अवसंरचना (ADI) समाधान: कृषि को बढ़ावा देने और ज्ञान को अधिक से अधिक साझा करने हेतु शुरू की गई है।

□ प्रस्तावित नेशनल एग्री स्टैक: इससे किसानों को सर्वोत्तम इनपुट्स (जैसे- बीज की किस्में), सर्वोत्तम प्रथाएं, मौसम पर अपडेट, कृषि ऋण, बीमा आदि के चयन में मदद मिलेगी।

□ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल नुकसान के आकलन में तेजी लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों, जैसे- उपग्रह मानचित्रण, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

❖ **फिनटेक:** कई फिनटेक कंपनियां आसान एवं तीव्र बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल भुगतान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय प्रसार को बढ़ावा दे रही हैं। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता में वृद्धि होती है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं।

❖ **ट्रेस मैप्स (Trace Maps):** इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-III के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA) ने तैयार किया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क उपयोग की पहचान और गणना करने के लिए बस्तियों से निकटवर्ती सुविधाओं हेतु यातायात का अनुकरण करता है। इसके बाद इस जानकारी का उपयोग फील्ड इंजीनियरों को योजना बनाने में मदद करने हेतु महत्वपूर्ण मार्ग और प्रमुख ग्रामीण लिंक का सुझाव देने के लिए किया जाता है।

❖ **जियो-टैगिंग:** जियो-टैगिंग अलग-अलग परियोजनाओं की बेहतर निगरानी में मदद करती है और भ्रष्टाचार को कम करती है। PMGSY - III के तहत 7.70 लाख से अधिक ग्रामीण सुविधाओं, जैसे- चिकित्सा, शिक्षा और बाजार को जियो-टैग किया गया है। मनरेगा (MGN-REGA) के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों (जैसे- जल संचयन, सूखा राहत, बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों आदि) को भी जियो-टैग किया जा रहा है।

» **चुनौतियां, जो प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर उपयोग और उन्हें अपनाने में बाधा डालती हैं:**

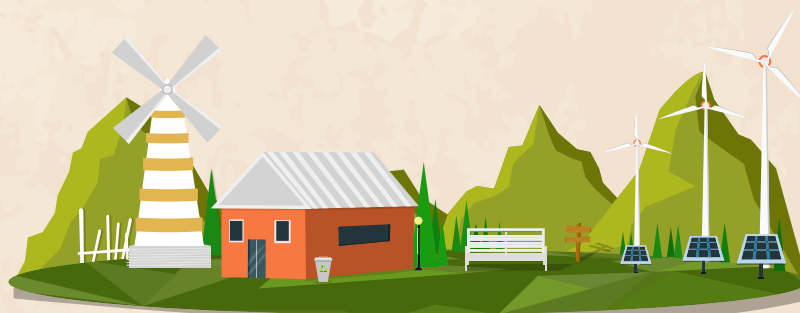
❖ प्रौद्योगिकी अपनाने की उच्च लागत;

❖ तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान का अभाव;

❖ लघु भू-जोत, फसल पद्धतियों की विविधता और बाजार की खामियों के कारण डिजिटल कृषि के इस्तेमाल में कठिनाई आदि।

ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने और इसे तीव्र करने हेतु क्या करने की आवश्यकता है?

- ❖ **ग्रामीण औद्योगिक नीति का निर्माण:** लघु अवधि के लक्ष्यों और लंबी अवधि के विजन के साथ एक समेकित रणनीति तैयार की जानी चाहिए।
- ❖ **ग्रामीण उद्योगों को परिभाषित करना:** बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), 1977 के अनुसार कुटीर और लघु उद्योगों का वर्गीकरण वर्तमान समय के लिए उपयुक्त नहीं है। वैश्वीकरण के संदर्भ में सामान्य रूप से ग्रामीण उद्योगों को परिभाषित करना समय की मांग है।
- ❖ **तकनीकी उन्नयन:** उत्पादन की तकनीकों के उन्नयन से ग्रामीण उद्यमों की उत्पादन क्षमता और उत्पादों की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार होंगे।
- ❖ **ग्रामीण कौशल विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण:** नई शिक्षा नीति 2020 सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह नीति स्कूली और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करती है। अल्पावधि में, ग्रामीण कार्यबल को प्रभावी ढंग से कौशल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलें करने की आवश्यकता है:
 - ❖ उपयुक्त सेवाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में सक्षम होने के लिए लिंग, आयु, नृजातीयता, दिव्यांगता एवं अन्य प्रासंगिक आयामों के आधार पर अलग-अलग डेटा एकत्र करना तथा उसका विश्लेषण करना।
 - ❖ विभिन्न अवसरों और अनेक सरकारी कौशल पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
 - ❖ निजी क्षेत्र के साथ समन्वय और सहयोग को मजबूत करना।
 - ❖ श्रम बाजार की आवश्यकताओं और आर्थिक अवसरों का आकलन करना तथा विशेषकर ग्रामीण संदर्भ में प्रशिक्षण को कौशल आवश्यकताओं से जोड़ना।
- ❖ **ग्रामीण महिलाओं की क्षमता का दोहन:** भारत सरकार अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू कर रही है। ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक कल्याण के पहलुओं के विस्तार पर केंद्रित हैं। इन सभी प्रयासों को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करते समय विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण महिलाओं की सामूहिक सौदेबाजी और सामाजिक संवाद को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- ❖ **अवसंरचना में कमियों को पूरा करना**
 - ❖ **मजबूत पश्चगामी (बैकवर्ड) और अग्रगामी (फॉरवर्ड) लिंकेज:** कच्चे माल (इनपुट्स) के लिए एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादों के लिए विपणन के अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता है।
 - ❖ **ग्रामीण-शहरी लिंकेज:** खेत से छोटे कस्बों तक और आगे बड़े शहरों तक ग्रामीण-शहरी लिंकेज को मजबूत करने से ग्रामीण श्रम उत्पादन, वितरण, बाजार, सेवाओं, उपभोग आदि को लाभ होगा।
 - ❖ **डिजिटलीकरण:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण न केवल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उत्पाद की प्रभावी ब्रांडिंग और विपणन सुनिश्चित करेगा।
- ❖ **सहकारी संघवाद:** ग्रामीण औद्योगीकरण के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा आरंभ की गई अलग-अलग पहलों को राज्य सरकारें लागू करती हैं। इस कारण केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग इन पहलों की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- ❖ **MSMEs की भूमिका को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:**
 - ❖ आवश्यक अवसंरचना निर्माण के लिए भारी निवेश करना;
 - ❖ MSMEs को प्रौद्योगिकियों, वित्त और बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाने के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करना; तथा
 - ❖ व्यावसायिक शिक्षा एवं विनिर्माण और व्यवसाय योजना निर्माण में कौशल विकास करना।
- ❖ **ग्रामीण उद्योगों की निर्यात क्षमता का उपयोग करना:** भारत के पारंपरिक खादी और हस्तशिल्प, हथकरघा, कोंयर उद्योग तथा प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में निर्यात की अपार क्षमताएं मौजूद हैं। इन क्षमताओं का दोहन विदेशों में संभावित बाजारों में मांग की पहचान करके, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से विपणन करके और उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण के द्वारा किया जा सकता है।
- ❖ **कोविड-19 द्वारा उत्पन्न अवसरों पर बैंकिंग:** ग्रामीण प्रवासी कामगारों को ऋण, तकनीकी जानकारी और बाजार सहायता प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्हें एकीकृत करने तथा MSMEs इकाइयों की स्थापना के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है।



एक छोटी सी वार्ता! ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग



विनय: हाय विनी। केरल की यात्रा कैसी रही?

विनी: हाय विनय! वह शानदार थी। मैं एर्नाकुलम गई थी और वहां एक स्थानीय गांव में रही, जिसे कुंबलंगी के नाम से जाना जाता है।

विनय: अरे वाह! ये भारत का पहला इको-टूरिज्म गांव है?

विनी: हाँ विनय! इस गांव ने स्वयं को एक छोटे द्वीप से मछली पकड़ने के एक आदर्श गांव और इस तरह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल में बदलने तक का एक लंबा सफर तय किया है।

विनय: इस गांव में ऐसा अनोखा क्या है?

विनी: यह संधारणीय ग्रामीण पर्यटन के लिए अनुकरणीय मॉडल है। यहां प्लास्टिक पर प्रतिबंध है और कृत्रिम रूप से निर्मित पर्यटन संरचनाएं, जैसे रिसॉर्ट या कॉटेज नहीं हैं। मैंग्रोव, पूमीन चट्टम (उच्च ज्वार के दौरान अर्द्ध चक्र में मछलियों के समूह की आवाजाही) और सी-स्पाकल (जिसे स्थानीय रूप से 'कवारु' के रूप में जाना जाता है) कुंबलंगी के बैकवाटर में बहुत ही मनोरम दृश्य थे।

विनय: वाह, यह आकर्षक लगता है विनी! विश्वास नहीं होता कि एक भारतीय गांव के पास देने के लिए इतना कुछ है।

विनी: बिल्कुल! मैं वहां एक यात्री से भी मिली, जिसने मुझे भारत के कुछ अन्य संभावित गांवों जैसे ज्योतिसर (हरियाणा, गीता का जन्म स्थान) तथा पारंपरिक शिल्प और कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध होडका (गुजरात) के बारे में बताया। ये गांव पूरी तरह से विकसित होने पर पर्यटन के विभिन्न अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।

विनय: ठीक है! लेकिन, केरल मॉडल को पूरे देश में लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि अधिकतर गांवों में पर्यटन का समर्थन करने वाला बुनियादी ढांचा या तो अपर्याप्त है या पूरी तरह से अनुपस्थित है।

विनी: क्या तुम भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप योजना के बारे में जानते हो।

मुझे विश्वास है कि यह भारत में ग्रामीण पर्यटन को गति प्रदान करेगा।

विनय: ऐसा है क्या? क्या तुम मुझे इस पहल के बारे में कुछ और बता सकती हो?

विनी: यह योजना प्रमुख घटकों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की एक रूपरेखा तैयार करती है। इन घटकों में ग्रामीण पर्यटन के लिए आदर्श नीतियां और सर्वोत्तम प्रथाएं, डिजिटल तकनीक एवं प्लेटफॉर्म, क्लस्टर विकसित करना, विपणन सहायता प्रदान करना, हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना, गवर्नेंस तथा संस्थागत ढांचा शामिल हैं।

विनय: यह बहुत अच्छी पहल है। हालांकि, इस तरह की पहल को सफल बनाने के लिए लोगों की भागीदारी और समर्थन भी जरूरी है।

विनी: यह सच है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमें ग्रामीण भारत के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा।



निष्कर्ष

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कृषि अकेले भारत में जनसंख्या के बड़े हिस्से को जीवित रखने में असमर्थ है। इसलिए, गैर-कृषि रोजगार के अधिक अवसरों का दोहन करने की आवश्यकता है। ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि इसमें न केवल लाखों दस्तकारों के मौजूदा समूह को बनाए रखने की कुंजी है, बल्कि यह बड़ी संख्या में नए प्रवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विचारशील नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण, पड़ोसी शहरी क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ आर्थिक एकीकरण, नवाचारों का समर्थन, स्टार्टअप्स और डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं और ग्रामीण-शहरी असमानताओं को भी कम किया जा सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में एक अच्छा कदम होगा।

टाँपिक – एक नज़र में

ग्रामीण उद्योग गैर-कृषि गतिविधियां होती हैं। ये ग्रामीण संसाधनों पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण उद्योग सामान्यतः जनता द्वारा उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये मुख्यधारा के उद्योगों के विपरीत हैं, जहां वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।
अलग-अलग प्रकार के ग्रामीण उद्योगों में पारंपरिक उद्योग (जैसे खादी उद्योग), हल्के उद्योग (जैसे पशु चारा उद्योग), मध्यम समूह के उद्योग (जैसे लघु सीमेंट संयंत्र), भारी उद्योग (जैसे जैव-उर्वरक संयंत्र) और सनराइज क्षेत्र के उद्योग (जैसे ग्रामीण पर्यटन) शामिल हैं।



राष्ट्रीय विकास में ग्रामीण औद्योगीकरण की भूमिका

- ❖ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण।
- ❖ अतिरिक्त और गैर-मौसमी रोजगार प्रदान करना तथा किसानों की कृषि आय को संपूरित करना।
- ❖ समावेशी राष्ट्रीय विकास।
- ❖ संतुलित औद्योगीकरण।
- ❖ भारत की समृद्ध संस्कृति का संरक्षण।
- ❖ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को बढ़ावा।
- ❖ महिला सशक्तीकरण।
- ❖ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।



स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण उद्योगों के लिए ढांचे का विकास

ग्रामीण उद्योगों का संरक्षण –
1947–56

↓
ग्रामीण उद्योगों का विकास –
1956–61

↓
ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा –
1961 से आगे



ग्रामीण उद्योगों की सफलता की राह में प्रमुख बाधाएं

- ❖ संरक्षण के कारण बेहतर स्पर्धा न कर पाना: 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद घरेलू बाजार में लघु उद्योगों (SSIs) के लिए आरक्षित मर्दों को आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी
- ❖ समय पर पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में असमर्थता।
- ❖ विपणन, परिवहन, वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं आदि हेतु अपर्याप्त अवसंरचना।
- ❖ शहरी उद्योगों से कच्चे माल की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धा।
- ❖ उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाने में असमर्थता।
- ❖ स्थानीय प्रतिभाओं को बनाए रखने या बाहर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने में असमर्थता।



चुनौतियों से निपटने और ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें

- ❖ औपचारिक संस्थागत व्यवस्था: KVIC और NSIC लिमिटेड।
- ❖ पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना: स्फूर्ति (SFURTI) और उस्ताद (USTTAD) योजना।
- ❖ छोटे उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं को सुगम बनाना: नाबार्ड और सिडबी की स्थापना, सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना आदि।
- ❖ प्रशिक्षण प्रदान करना और कौशल का विकास करना: सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPs), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) आदि।
- ❖ कृषि आधारित उद्योगों के लिए योजनाएं: कृषि आधारित उद्योगों के लिए एस्पायर योजना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएम संपदा योजना आदि।
- ❖ उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना: अटल नवाचार मिशन (AIM) के माध्यम से इन्क्यूबेशन सेंटर का विकेंद्रीकरण करना, स्टार्टअप इंडिया योजना आदि।
- ❖ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण, अवसंरचना निर्माण, डिजिटल सशक्तीकरण आदि के लिए अन्य पहलें।



ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने और इसे तीव्र करने के लिए आगे की राह

- ❖ ग्रामीण औद्योगिक नीति का निर्माण करना।
- ❖ ग्रामीण उद्योगों को परिभाषित करना।
- ❖ उत्पादन की तकनीकों का उन्नयन करना।
- ❖ कौशल विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना।
- ❖ ग्रामीण महिलाओं की क्षमता का दोहन करना।
- ❖ अवसंरचना संबंधी अंतरालों को समाप्त करना।
- ❖ अन्य पहलें जैसे कि सहकारी संघवाद, MSMEs की भूमिका को मजबूत करना, ग्रामीण उद्योगों की निर्यात क्षमता का दोहन करना, कोविड-19 द्वारा उत्पन्न अवसरों पर बैंकिंग आदि ने रिवर्स माइग्रेशन को प्रेरित किया है।

FOR DETAILED ENQUIRY, PLEASE CALL:
+91 8468022022, +91 9019066066
ENQUIRY@VISIONIAS.IN © Vision IAS
www.visionias.in



DELHI



JAIPUR



HYDERABAD



PUNE



AHMEDABAD



LUCKNOW



CHANDIGARH



GUWAHATI



ENQUIRY@VISIONIAS.IN



/C/VISSIONIASDELHI



/VISION_IAS



VISION_IAS



WWW.VISIONIAS.IN



/VISIONIAS_UPSC